सच्चाई के दम पर
जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्य: ` 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, शुक्रवार , 26 दिसंबर, 2025
वर्ष: 03, अंक: 1, पृष्ठ: 8+4

विवाद के बाद कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज से मांगी माफी

» Pg 9

इनसाइड विकास की दौड़ में 'हांफ' रहा बिल्हौर » Pg03

नगर निगम सदन में हंगामा, दो पार्षद निलंबित

» हंगामा होने की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा

» पार्षद दल के नेता ने कहा दोनों पार्षदों का यह रवैया पहली बार नहीं है

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम कानपुर का सदन शुक्रवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही के दौरान अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षदों को चार सदनों के लिए निलंबित कर दिया गया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी और अंततः सदन को स्थगित करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब मेयर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में आहूत नगर निगम सदन में कार्यसूची के प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान वार्ड 4 ग्वालटोली अंकित मौर्य और वार्ड 37 के पार्षद पवन गुप्ता द्वारा लगातार शोरगुल, आपसी नोकझोंक और अभद्र व्यवहार किया गया। बार-बार समझाने के बावजूद स्थिति नहीं संभली, जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई।पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने बताया कि दोनों पार्षदों का यह रवैया पहली बार नहीं है। पूर्व में भी कई बैठकों में इसी तरह के आचरण के कारण महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर चर्चा बाधित होती रही है। इस बार स्थिति तब और गंभीर हो गई जब राष्ट्रगान के समय भी शोरगुल बंद नहीं हुआ और आपत्तिजनक व्यवहार किया गया, जिससे सदन में मौजूद अन्य पार्षदों और अधिकारियों में रोष फैल गया।लगातार हंगामे और अनुशासनहीनता को देखते हुए पीठ द्वारा दोनों पार्षदों को चार आगामी सदनों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इसके बावजूद माहौल शांत नहीं हो सका और कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। अंततः सदन को स्थगित करना पड़ा।नगर निगम सूत्रों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल सदन की कार्यवाही को प्रभावित करती हैं, बल्कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में भी अनावश्यक देरी का कारण बनती हैं। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

> पार्षद अंकित मौर्य ने कहा कि मेरे वार्ड में विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है, सदन में बात रखने का प्रयास किया तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, मैने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है।
>
> पार्षद पवन गुप्ता ने कहा कि मैं भाजपा का पार्षद हूं, मेरे वार्ड में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, जनता हमसे नाराज होती है, मेरे द्वारा सदन में अपनी बात रखी गई है, जानबूझकर हमे झुकाया जा रहा।

-: संदेश :-

कानपुर और लखनऊ से संयुक्त रूप से प्रकाशित सांध्य दैनिक स्वराज इंडिया 26 दिसंबर 2025 को अपने गौरवपूर्ण तीन वर्ष पूरे कर रहा है। यह सफर सिर्फ समय का नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और सतत प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

इस विशेष अवसर पर हम अपने सम्मानित पाठकों, विज्ञापनदाताओं, शुभचिंतकों और सहयोगियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और अनंत शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं। आपके साथ और समर्थन ने ही **स्वराज इंडिया** को निरंतर सशक्त किया है।

सीमित संसाधनों में लगातार मेहनत, सत्य के प्रति निष्ठा और निष्पक्ष पत्रकारिता की दिशा में अदम्य समर्पण दिखाने के लिए संपादकीय, विज्ञापन, प्रबंधन टीम तथा सभी सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन। इन्हीं की प्रतिबद्धता ने **स्वराज इंडिया** को उत्तर भारत के सांध्य दैनिकों में विशिष्ट और विश्वसनीय स्थान दिलाया है।

हम वचन देते हैं कि पाठकों का विश्वास हमारी दिशा भी तय करता रहेगा और प्रेरणा भी देता रहेगा। सत्य, निष्पक्षता और जनसरोकार की पत्रकारिता को और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प अटूट है।

**स्याही में सिर्फ़ शब्द नहीं, सच का उजाला बसता है,
जो हर शाम पाठकों के दिलों में नया भरोसा रचता है।**

स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

प्रधान संपादक
पुरुषोत्तम द्विवेदी

स्थानीय संपादक
अनूप कुमार

बांग्लादेश में फिर हिंदू युवक की भीड़ ने कर दी मॉब लिंचिंग

» राजबाड़ी जिले में रात 11 बजे भीड़ का हमला, 29 वर्षीय सम्राट मंडल की मौके पर मौत

» दीपू चंद्र दास मामले के बाद फिर उठा हिंसा का साया, पुलिस पर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बांग्लादेश में एक बार फिर उग्रवादियों की भीड़ ने हिंदू युवक को निशाना बनाया है। राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला के होसैंदंगा पुराने बाजार में देर रात 29 वर्षीय सम्राट मंडल उर्फ अमृत मंडल को घेरकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों ने उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में हिंदू समुदाय पर लगातार हमलों के चलते भय और तनाव का माहौल बन गया है। इससे पहले दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद भी बांग्लादेश प्रशासन सवालों के घेरे में था।

अपराध, विवाद और पुलिस कार्रवाई

स्थानीय सूत्रों के अनुसार सम्राट मंडल पर 'सम्राट वाहिनी' नामक गिरोह चलाने और वसूली के आरोप पहले से लगे थे। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम वह अपने साथियों के साथ एक ग्रामीण से पैसे वसूलने पहुंचा, जहां शोर मचने पर ग्रामीण एकत्र हो गए और भीड़ ने उसकी पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गिरोह के अन्य सदस्य मौके से भाग निकले, जबकि पुलिस ने सम्राट के एक साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। लगातार होती ऐसी घटनाओं ने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिल्कोमोर
पशु आहार

दूध बहेगा,
मुनाफा बढ़ेगा..

संपर्क करें
9310500105

निर्माता:
कपिला
कृषि उद्योग लि.

विश्वसनीयतम उत्पाद | सबसे ज्यादा पोषण 75% | अच्छा स्वास्थ्य | ज़्यादा दूध | लंबी आयु

दुकानदार भाई!
Badho App से ऑर्डर लगायें और
पायें हर ऑर्डर पर आकर्षक स्कीम

Google Play
App Store

अलविदा 2025 : वादों और दावों के बीच झूलता रहा साल

विकास की दौड़ में 'हांफ' रहा बिल्हौर

रिजवान कुरैशी/ स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर। साल 2025 विदा होने को है, लेकिन कानपुर नगर की सबसे बड़ी तहसील बिल्हौर के लिए यह साल भी उम्मीदों और हताशा के बीच झूलता रहा। एक तरफ सरकारें आधुनिक बुनियादी ढांचे का दावा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिल्हौर तहसील बुनियादी सुविधाओं के शून्य पर खड़ा नजर आता है।बाईपास ने जहां एक ओर रफ्तार छीनकर लोगों को पैदल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग की बसों के बिल्हौर से चोरी छिपे निकलने से बिल्हौर की जनता के लिए सबसे बड़ा दर्द परिवहन रहा। बाईपास बनने के बाद रोडवेज बसों ने शहर के अंदर आना लगभग बंद कर दिया है। कभी शान से चलने वाली सीएनजी बसें अब सड़कों से गायब हैं।

- **कानपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील-फिर भी सुविधाओं के लिए तरस रहे लोग**
- **आखिर कब आएगा लोगों का दर्द सुनने वाला, अब तो उम्मीदें भी लगने लगी हैं झूठी**

आलम यह है कि कानपुर जैसे महानगर से सटे होने के बावजूद, यहाँ के यात्रियों को डग्गामार वाहनों का घंटों सहारा करना पड़ रहा है। नगर में स्थाई टेंपो स्टैंड और स्थाई बस स्टॉप तक न होना प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।और यहाँ के नेताओं पर भी। यातायात के दूसरे प्रमुख साधनों में गिना जाने वाला भारतीय रेल भी सुविधाओं के नाम पर नाकाफी है। कहने के लिए यहां से होकर कई ट्रेनें देश के तमाम प्रमुख शहरों को जाती हैं लेकिन उनका ठहराव बिल्हौर में नहीं है। कुछ ट्रेनों का ठहराव सांसद अशोक रावत ने बिल्हौर में कराया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब यह ट्रेनें कानपुर की ओर बढ़ती हैं तो कानपुर के प्रमुख स्टेशन कल्याणपुर और रावतपुर में इनका स्टॉपेज नहीं है। छपरा मथुरा जैसी ट्रेन का अप डाउन दोनों में ही कल्याणपुर ठहराव होना जरूरी है। सरकारी नौकरी करने वालों का एक बड़ा वर्ग इस ट्रेन का लाभ उठा सकता है। अभी इन यात्रियों को अनवरगंज तक की दौड़ लगानी पड़ती है।

बालिका शिक्षा पर सबसे बड़ा ब्रेक डिग्री कॉलेज का अभाव

शिक्षा के मामले और बालिका शिक्षा के मामले में भी बिल्हौर अभी तक किशोरावस्था में है। यहां पर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। जिसके चलते अधिकांश बालिकाओं को इंटर के बाद घरों में बैठना पड़ता है। इक्का दुक्का प्राइवेट डिग्री कॉलेज अरौल में हैं जहां पर अभिभावक अपनी बेटियों को भेजने में झिझकते हैं। बिल्हौर के युवाओं के लिए एक स्टेडियम की स्थापना कराए जाने की मांग और वादे कई साल

से किए जा रहे हैं लेकिन अबकी वर्ष भी यह सपना अधूरा ही रह गया।

कानपुर नगर में होने के बावजूद माती जाने की मजबूरी

बिल्हौर की जनता के लिए इस साल भी सबसे बड़ा सिरदर्द न्यायिक कार्यों के लिए माती (कानपुर देहात) जाना रहा। भौगोलिक रूप से कानपुर नगर का हिस्सा होने के बाद भी प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण लोगों को मीलों दूर माती दौड़ना पड़ता है। यह न केवल धन की बर्बादी है, बल्कि समय की भी भारी क्षति है।

दशकों पुरानी तहसील, आज भी अधूरी

दशकों पहले बिल्हौर तहसील तो बन गई, लेकिन यहाँ तैनात अधिकारियों के लिए ढंग के आवास आज तक नहीं बन पाए हैं। जिसका नतीजा यह है कि अधिकारी क्षेत्र में रुकने के बजाय शहर से अप-डाउन करते हैं।अधिकारियों की छोड़ो कर्मचारी तक देर सबेर आते हैं और वापस जाने की जल्दी में रहते हैं। ऐसी स्थिति में ?बिल्हौर को जिला बनाने की मांग अब कोई राजनीतिक स्टंट नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। जब तक प्रशासनिक ढांचा नहीं सुधरेगा, विकास की बातें बेमानी हैं।

इस समय प्रशासन ने रजिस्ट्री दफ्तर नगर सीमा से दो किलोमीटर दूर बनाने का निर्णय लिया तो वकील सड़कों पर उतर आए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। देखना यह है कि जीत प्रशासन की होती है कि वकीलों की। स्थानीय स्तर पर नेता सियाराम कठेरिया बिल्हौर को जिला बनाने के संघर्ष में जुटे हैं। अब देखना यह है कि वर्ष 2026 में बिल्हौर के हिस्से कुछ उपलब्धियां आती हैं या फिर यह साल भी उम्मीदों के सहारे ही गुजर जाता है।

साल 2026 में पब्लिक की उम्मीदें

- बसों का नगर के अंदर ठहराव अनिवार्य हो
- सीएनजी बसों का संचालन दोबारा शुरू किया जाए। स्थाई बस स्टॉप बने
- न्यायिक कार्यों को सुगम बनाया जाए और माती की निर्भरता खत्म हो।
- युवाओं के लिए खेल स्टेडियम और अधिकारियों के लिए स्थाई निवास बने।

जालौन में बदमाशों की पोल खोल रही पुलिस, मुनादी कर गांव वालों को कर रही सतर्क

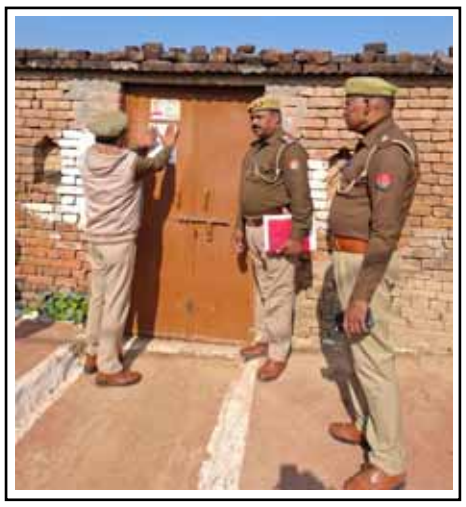

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जालौन। जनपद में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक सख्त और प्रभावी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब बदमाशों की पहचान छिपी नहीं रहेगी। पुलिस सीधे उनके घर और गांव पहुंचकर मुनादी करा रही है, ताकि आसपास के लोग भी उनकी आपराधिक करतूतों से वाकिफ हो सकें।कानपुर जोन में तैनात एडीजी आलोक सिंह के निर्देशन में, आईजी आकाश कुलहरि और एसपी डॉ दुर्गेश कुमार के मार्गदर्शन में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो अपराधी अपने गांव या मोहल्ले में खुद को शरीफ बताकर रखते हैं और बाहर जाकर लूट, चोरी, बलात्कार या गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी असलियत सार्वजनिक की जा सके।

पुलिस का मानना है कि कई अपराधी अपने ही इलाके में पहचान छिपाकर रखते हैं और दूसरे क्षेत्रों में जाकर वारदात करते हैं। इससे वे अपने गांव में संदेह के दायरे से बाहर रहते हैं। अब इस रणनीति पर पुलिस ने करारा प्रहार किया है। मुनादी अभियान के जरिए गांव और मोहल्ले के लोगों को बताया जा रहा है कि उनका पड़ोसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि गंभीर अपराधों का आरोपी है।इसी क्रम में गुरुवार को चुर्खी थानाध्यक्ष शिवशंकर ने थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरी जरहा में कार्रवाई की। यहां गैंगरेप के आरोपी गौरव पुत्र जीत सिंह के घर पहुंचकर पुलिस ने मुनादी कराई। इस दौरान आरोपी के आपराधिक कारनामों की पूरी फेहरिस्त गांव वालों को सुनाई गई। साथ ही बीएनएसएस की धारा 84 के तहत की गई कार्रवाई को चस्पा कर पूरे गांव में उद्घोषणा कराई गई।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान से न केवल अपराधियों पर मानसिक दबाव बनेगा, बल्कि गांव और मोहल्ले के लोग भी सतर्क रहेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने घर से गायब मिलता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जा सकेगी, जिससे किसी बड़ी वारदात को पहले ही रोका जा सके।जालौन पुलिस का यह कदम अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सख्त और असरदार पहल माना जा रहा है, जिसकी चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है।

हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे...

नशे में धुत युवकों ने पुलिस से बदसलूकी की खुद को वकील बताया, चारों गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर) ।कस्बा बिल्हौर में रात्रि गश्त के दौरान नशे में धुत चार युवकों ने पुलिस से अभद्रता करते हुए धमकी दी और जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों का 170 बीएनएस के तहत चालान किया।

पुलिस के अनुसार 25 दिसंबर की रात संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान कानपुर नगर की ओर से आ रही कार तेज गति से व लहराते हुए दिखाई दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक ने अनामिका पैलेस के सामने अस्थायी रूप से बनी लकड़ी की गुमटी में कार ठोक दी, जिससे गुमटी पलट गई और वाहन चालक वहीं रुक गया। कार से उतरे चारों युवक अत्यधिक नशे की हालत में थे। नाम-पता पूछने पर उन्होंने पुलिस से विवाद शुरू कर दिया और स्वयं को सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट का वकील बताते हुए कहा कि तुम लोगों की औकात नहीं है तुम हमारा नाम पूछो हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे । इसके बाद युवक आपस में भी हाथापाई पर उतर आए, जिससे उन्हें हल्की चोटें आईं। साथ ही पुलिस पर मारपीट और वाहन टक्कर कराने का आरोप लगाने लगे। पुलिस ने सूझबूझ से स्थिति को संभालते हुए युवकों को शांत कराया।

पूछताछ में उनके नाम आशीष निवासी रामपुर (कन्नौज), हर्षित कुमार निवासी सरायमीरा (कन्नौज), गोपेश्वर यादव निवासी सिरसागंज (फिरोजाबाद) तथा हरिओम चौरसिया निवासी छिबरामऊ (कन्नौज) बताए गए। इसके बाद चारों दोबारा झगड़ा-फसाद पर आमादा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाने की पुलिस बुलाई गई और चारों को हिरासत मे ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चारों पर शांति भंग की कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है।

ग्राम सभा की भूमि पर चला बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण

प्रशासन ने अवैध बाउंड्री गिराकर जमीन कराई कब्जा मुक्त

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर नगर)। तहसील क्षेत्र में सरकारी और ग्राम सभा की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को बिल्हौर तहसील के ग्राम मनावां स्थित ग्रामसभा की भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर उसे कब्जा मुक्त कराया गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 504ख (कुल रकबा 5.900 हेक्टेयर) आबादी के रूप में दर्ज है, जिसका एक हिस्सा लंबे समय से खाली पड़ा था। इस खाली भूमि के लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कुछ लोगों द्वारा चाहरदीवारी खड़ी कर अवैध कब्जा कर लिया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में थाना ककवन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। नायब तहसीलदार बिल्हौर चंद्र प्रकाश राजपूत के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने थाना ककवन व बिल्हौर पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

इस संबंध में उप जिलाधिकारी बिल्हौर संजीव दीक्षित ने स्पष्ट किया कि तहसील क्षेत्र में सरकारी अथवा ग्राम सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सम्पादकीय

पंजाब के किसानों को आर्थिक संबल जरूरी

एक समय था जब पंजाब के ग्रामीण अंचलों में खिले हुए सरसों के खेत मौसमी बयार में बदलाव के प्रतीक हुआ करते थे। तमाम सांस्कृतिक प्रतिमानों में पीले सरसों के खेतों को मौसम के गौरव के रूप में चित्रित किया जाता रहा है। लेकिन वक्त की विडंबना है कि यह अब यह सुनहरी फसल सिमटती नजर आ रही है। जिसके परिणाम स्वरूप आज देश में हम खाद्य तेलों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि भारत लगातार आयातित खाद्य तेलों पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। निश्चय ही यह स्थिति व्यवस्था के कई विरोधाभासों को भी उजागर कर रही है। यह तथ्य चौंकाता है कि पंजाब में सरसों के उत्पादन में इसलिए गिरावट नहीं आ रही है कि फसल उत्पादन क्षमता में किसी तरह की कोई कमी आई है। बल्कि यह स्थिति इसलिए है कि सरकारों की नीतियां प्रोत्साहन देने वाली साबित नहीं हो रही हैं। वहीं बाजार के रुझान इसे आर्थिक रूप से किसानों के हितों के प्रतिकूल बना रहे हैं। कहने को तो अकसर दलील दी जाती है कि पंजाब के किसानी से जुड़े संकटों का समाधान फसलों के विविधीकरण में निहित है। लेकिन विडंबना यह है कि विविधीकरण के दावों के बावजूद, सरसों के उत्पादक किसान प्रोत्साहन न मिल पाने से निराश हैं। दरअसल, किसान कम और अनिश्चित मुनाफे के चलते सरसों की फसल उगाने से गुरेज करता है। जिसके चलते किसानों को खून-पसीने की उपज को बेचने के लिये व्यापारियों के रहमोकरम पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने मोटे मुनाफे के लिये किसान के हितों की अनदेखी करने से नहीं चूकते। यही वजह है कि गेहूं और धान के विपरीत, जिनकी खरीद सुनिश्चित है और उनके लिये मजबूत विपणन प्रणाली मौजूद है, सरसों की फसल किसानों को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना देती है। फलतः किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल, इस संकट का दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब आज अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का एक मामूली हिस्सा ही स्थानीय उत्पादन से पूरा करता है। इससे हमारी महंगे आयात पर निर्भरता और भी बढ़ जाती है। तिलहन की खेती को बढ़ावा देना अक्सर राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही मायनों में सरकारी तंत्र द्वारा सरसों की उपज की खरीद में सहायता और न्यायसंगत मूल्य दिलाने के वायदे खोखले साबित होने के कारण सरसों की पैदावार का रकबा बढ़ता नहीं है। जिस दिन किसानों को तंत्र की नीतियों पर भरोसा पैदा हो जाएगा, उस दिन निश्चय ही किसान प्रोत्साहन के चलते तर्कसंगत प्रतिक्रिया देंगे। निर्विवाद रूप से पंजाब की धरती में सरसों उत्पादन की स्थितियों से जुड़ी संभावनाएं पर्याप्त हैं। यकीनी तौर पर यह धान की तुलना में कम पानी की खपत करती है। साथ ही भूजल संकट को कम करने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण से जुड़ी रणनीतियों में स्वाभाविक रूप से फिट बैठती है। लेकिन हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि पंजाब में विविधीकरण के लक्ष्य केवल नैतिक प्रोत्साहन से हासिल नहीं किए जा सकते।

रचनात्मकता में एआई के उपयोग की सीमा का प्रश्न

ज्योति मल्होत्रा

जब हर क्षेत्र में एआई का उपयोग बढ़ रहा है तो सवाल है कि रचनात्मकता यानी साहित्य व कला के संदर्भ में एआई का कितना उपयोग स्वीकार्य है। दरअसल, मानव सृजनात्मकता पर एआई के आक्रमण के प्रतिरोध और स्वीकृति... जब हर क्षेत्र में एआई का उपयोग बढ़ रहा है तो सवाल है कि रचनात्मकता यानी साहित्य व कला के संदर्भ में एआई का कितना उपयोग स्वीकार्य है। दरअसल, मानव सृजनात्मकता पर एआई के आक्रमण के प्रतिरोध और स्वीकृति का स्तर, समय व भूगोल के साथ बदलता रहता है। हालांकि कला क्षेत्र में रचनात्मकता को गंभीर मिलावट से तब तक बचाना चाहिये जब तक यह एक नई तरह की कला के लिए राह न खोल दे।

एक दिलचस्प समाचार के रूप में, न्यूजीलैंड के दो पुरस्कार विजेता लेखकों की किताबों, स्टेफनी जॉनसन के लघु कहानी संग्रह 'ओब्लिगेट कार्निवोर' और एलिजाबेथ स्मिथर के उपन्यास संग्रह 'एंजेल ट्रेन', को कृत्रिम बुद्धि (एआई) के उपयोग के कारण 65 हज़ार न्यूज़ीलैंड डॉलर पुरस्कार राशि वाले 2026 ओखम बुक अवॉर्ड्स (फिक्शन), जो देश का शीर्ष साहित्यिक पुरस्कार है, के लिए विचार करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह अस्वीकृति लेखन में एआई के उपयोग को लेकर नहीं बल्कि पुस्तकों के कवर डिज़ाइन के कारण हुई, जो एआई उपयोग संबंधी नए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते पाए गए। स्वाभाविक ही इस एआई युग में यह सवाल उठता है कि रचनात्मकता के संदर्भ में एआई का कितना उपयोग स्वीकार्य है। लक्ष्मण रेखा कहां होनी चाहिए? मानव रचनात्मकता पर एआई के आक्रमण के प्रतिरोध और स्वीकृति का स्तर, समय और भूगोल के साथ बदलता रहता है। जर्मन फ़ोटोग्राफ़र बोरिस एल्डैग्सन 2023 में तब एक व्हिसलब्लोअर बन गए, जब उन्होंने सोनी वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी अवार्ड्स में क्रिएटिव ओपन श्रेणी का पुरस्कार यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि विजेता छवि बनाने के लिए उन्होंने एआई का उपयोग किया था। यांग ने एआई का उपयोग करके केवल तीन घंटों में 'लैंड्स ऑफ मेमोरी' नामक पुस्तक बना दी और इसने अक्तूबर 2023 में, जियांग्सू यूथ पॉपुलर साइंस फिक्शन प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता। इसके अलावा, यह स्वीकार करने के बाद भी कि उनके उपन्यास 'टोक्यो-टू डोजो-टू' का 5 फीसदी शब्दशः चैटजीपीटी द्वारा बनाया गया था, जापानी लेखिका री कुडन ने 2024 में अकुतागावा पुरस्कार जीता, जो जापान के प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मानों में से एक है! कुडन के अनुसार, उन्होंने 'नरम और अस्पष्ट' शब्द खोजने को एआई की मदद ली थी, वे जो उनके उपन्यास में व्याप्त न्याय की जटिल अवधारणाओं को समाहित करते हों, इसे चयन समिति ने 'कोई गलत नहीं' माना। खैर, एड्रियन ब्रॉडी ने 'द ब्रुटलिस्ट' फिल्म में अपने द्वारा अभिनीत भूमिका में हंगेरियन भाषा बोलते समय, उच्चारण बेहतर बनाने के लिए, एआई के उपयोग के बावजूद इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। इस वर्ष की अन्य ऑस्कर-नामांकित फिल्मों में, एआई क्लोनिंग का उपयोग जैक्स ऑडियार्ड के ट्रांसजेंडर गैंगस्टर म्युज़िकल एमिलिया पेरेज़ में कार्ला सोफिया गैसकॉन की गायन आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए भी किया गया था। क्या यह स्पष्ट संकेत है कि हॉलीवुड भी मात्र दो सालों में एआई को स्वीकार कर अपने अभिनेताओं और पटकथा लेखकों के दोहरे हमले को मान्यता दे रहा है, यह सुनिश्चित करने को कि चलो श्रमिकों ने अपना काम नई तकनीक से बदलने की बजाय उस पर नियंत्रण तो बनाए रखा इसके उल्ट, अकादमिक पत्रिकाएं इन दिनों शोध पत्रों में एआई के उपयोग के विरुद्ध सख्त रुख रखे हैं, हालांकि चैटजीपीटी को 2022 के अंत व 2023 के शुरू में प्रकाशित कई शोधपत्रों में सह-लेखक सूचीबद्ध किया गया।

वक्रव्यूह से मुक्त वसीयत का 'आजादी महोत्सव'

सरलीकरण से राहत

दीपिका अरोड़ा

भविष्य की कानूनी लड़ाइयों से बचने के लिए आज भी दो गवाहों की मौजूदगी में स्पष्ट वसीयत लिखना ही एकमात्र अचूक मंत्र है। कानून ने अनिवार्य प्रोबेट की लाठी छीन ली है, लेकिन समझदारी का छाता आपके हाथ में छोड़ दिया है। भारत में अपनी ही संपत्ति को अपनों के नाम छोड़ जाने की प्रक्रिया अक्सर एक कानूनी दुःस्वप्न बन जाती थी। लेकिन संसद ने 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' के जरिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की बेड़ियां काटकर एक नई सुबह का आगाज किया है।

सालों से चली आ रही 'प्रोबेट' की अनिवार्य शर्त को अब इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो, अब मरने वाले की अंतिम इच्छा यानी उसकी 'वसीयत' को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए अदालतों की लंबी कतारों और भारी-भरकम फीस से मुक्ति मिल गई है। सरल शब्दों में समझें तो 'प्रोबेट' अदालत द्वारा जारी किया गया वह प्रमाणपत्र है, जो कानूनी रूप से यह तस्दीक करता है कि वसीयत पूरी तरह असली है और इसे बनाने वाला व्यक्ति (वसीयतकर्ता) इसे लिखते समय पूरी तरह होश-ओ-हवास और सही मानसिक स्थिति में था। अब तक हमारा कानून एक अजीब विरोधाभास और 'क्षेत्रीय भेदभाव' का शिकार था। अगर आप मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे पुराने 'प्रेसिडेंसी टाउन्स' में रहते थे, तो वसीयत होने के बावजूद संपत्ति हस्तांतरण के लिए प्रोबेट लेना अनिवार्य था। यह प्रक्रिया किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी; इसमें न केवल सालों का समय बर्बाद होता था, बल्कि संपत्ति की कुल कीमत का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 2 से 5 प्रतिशत तक) भारी-भरकम 'कोर्ट फीस' और वकीलों के खर्च की भेंट चढ़ जाता था। 2025 का यह नया सुधार इसी विसंगति पर प्रहार करता है। अब चाहे आप दिल्ली के दिल में हों, पटना की गलियों में या मुंबई के समंदर किनारे- कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सरकार ने इस 'अनिवार्यता' को खत्म कर यह सुनिश्चित किया है कि अब विरासत पाने के लिए आपको अपनी ही जेब

खाली नहीं करनी पड़ेगी। यह ऐतिहासिक बदलाव रातो-रात नहीं आया, बल्कि इसके पीछे न्यायपालिका के दशकों पुराने कानूनी मंथन की गूंज है। इस सुधार की बुनियाद असल में साल 2001 में ही रख दी गई थी, जब 'क्लोरेंस पैस बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। हालांकि उस वक्त अदालत ने धारा 213 की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संकेत भी दिया कि प्रोबेट की अनिवार्यता केवल कुछ विशेष और सीमित परिस्थितियों के लिए ही तर्कसंगत हो सकती है। इस फैसले ने भविष्य के लिए एक नई बहस छेड़ दी थी - कि क्या एक निर्विवाद वसीयत के लिए भी अदालती मुहर हर हाल में जरूरी होनी चाहिए साल 2005 में 'मैरी कोचु बनाम थॉमस' जैसे मामलों में अदालतों ने और भी सख्त रुख अपनाया। केरल हाईकोर्ट और बाद के विभिन्न फैसलों में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि प्रोबेट की अनिवार्यता का नियम अक्सर न्याय दिलाने के बजाय केवल कानूनी पेचीदगियां और बोझ बढ़ाता है। हाल के वर्षों में तो सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह दोहराया कि यदि वसीयत की सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, तो वारिसों को जबरन अदालती चक्रव्यूह में घसीटना 'ईज ऑफ लिविंग' (सुगम जीवन) के बुनियादी सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है। 2025 के इस नए कानून ने असल में न्यायपालिका की इन्हीं प्रगतिशील टिप्पणियों और वर्षों की कानूनी जद्दोजहद को एक 'वैधानिक कवच' प्रदान कर दिया है। संसद ने अदालतों की उस मंशा को कानून का रूप दे दिया है, जो लंबे समय से आम आदमी को वसीयत के नाम पर होने वाली कानूनी प्रताड़ना से बचाना चाहती थी। धारा 213 के हटने से वसीयत अब एक बेहद शक्तिशाली दस्तावेज बन गई है। अब उत्तराधिकारी प्रोबेट के बिना भी सीधे संपत्ति का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और बैंक खातों का सेटलमेंट करा सकेंगे। प्रोबेट अब 'अनिवार्य' नहीं है, लेकिन 'अप्रासंगिक' भी नहीं है। भले ही सरकार ने इसे थोपना बंद कर दिया हो, लेकिन इसे बेकार समझना भारी भूल होगी। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की जरा भी आशंका है, तो प्रोबेट आज भी अदालत में सबसे मजबूत 'सुरक्षा कवच' है। विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी संपत्ति या आपसी अनबन की स्थिति में 'स्वैच्छिक प्रोबेट' कराना एक स्मार्ट मूव है- यह भविष्य के महंगे मुकदमों से बचने का एक सबसे सस्ता और पक्का बीमा है। निःसंदेह, सरकार का यह कदम संकेत देता है कि भविष्य 'डिजिटल उत्तराधिकार' का है। जब प्रोबेट की अनिवार्यता खत्म होती है, तो लोगों में वसीयत लिखने का उत्साह बढ़ेगा। मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि उनका जीवनभर का निवेश अब कानूनी दांव-पेंच में नहीं फंसेगा। संसद का यह फैसला 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' का जीवंत उदाहरण है, जिसने वसीयत को अदालती धूल और अंतहीन तारीखों से आजाद कर सीधे हकदारों को सौंप दिया है। यह कदम साहसिक है, लेकिन पाठकों को समझना होगा कि कानून 'सरल' हुआ है।

कृषक परिवारों के लिए राहत भरे फैसलों का रहा वर्ष 2025

सतत निगरानी से बदली तस्वीर

» 457 परिवारों तक पहुँची राहत, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में एक अप्रैल से अब तक 22.85 करोड़ का भुगतान

» सिर्फ नए नहीं, पुराने जख़्म भी भरे वर्षों से लंबित 15 प्रकरणों का डीएम कोर्ट से निस्तारण, दिलाया मुआवजा

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इस वर्ष जनपद में सिर्फ राहत वितरण की योजना नहीं रही, बल्कि वर्षों से लंबित, उलझे और तकनीकी आपत्तियों में फंसे मामलों के लिए न्याय की प्रक्रिया बनी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में एक अप्रैल से अब तक 457 प्रकरणों में 22.85 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इनमें 15 ऐसे प्रकरण शामिल हैं, जो कई वर्षों से लंबित थे और जिनका निस्तारण जिलाधिकारी न्यायालय में विस्तृत सुनवाई के बाद किया गया।

पिछले चार वर्षों के आंकड़े योजना के बढ़ते दायरे और प्रभाव को दर्शाते हैं। वर्ष 2021–22 में 105 आवेदकों को 5.25 करोड़ रुपये, 2022–23 में 167 आवेदकों को 8.35 करोड़ रुपये, 2023–24 में 231 आवेदकों को 11.55 करोड़ रुपये और 2024–25 में 275 लाभार्थियों को 13.75 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी। इस वर्ष की विशेषता यह रही कि नए मामलों के साथ-साथ उन प्रकरणों को भी प्राथमिकता दी गई, जो लंबे समय से तकनीकी कारणों से लंबित थे।जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इन मामलों के लिए एक विशेष मैकेनिज्म विकसित किया, जिसमें बीमा कंपनियों के निर्णय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, तिथियों की गणना और योजना के अनुबंध की शर्तों की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रत्येक प्रकरण में यह देखा गया कि दावा वास्तव में कब प्रस्तुत किया गया और देरी किस स्तर पर हुई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को समय पर न्याय और भरोसा देना भी है। ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी कारणों या प्रशासनिक देरी से दावे लंबित रह गए थे, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई कर वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी पात्र परिवार का अधिकार केवल फाइल या तारीख़ की वजह से न छूटे। शासन की मंशा के अनुरूप योजना का प्रभावी और संवेदनशील क्रियान्वयन प्राथमिकता रहेगा।

विशेष तथ्य

वर्षों से लंबित 15 प्रकरणों का निस्तारण जिलाधिकारी न्यायालय से

प्रत्येक प्रकरण की व्यक्तिगत सुनवाई

प्रशासनिक देरी और तकनीकी आपत्तियों को मानवीय दृष्टि से परखा गया

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कानपुर नगर सहायता वितरण का आंकड़ा

वित्तीय वर्ष।	लाभार्थी।	सहायता राशि
2021-22	105 लाभार्थी	5.25 करोड़ रुपए
2022-23	167 लाभार्थी	8.35 करोड़ रुपए
2023-24	231 लाभार्थी	11.55 करोड़ रुपए
2024-25	275 लाभार्थी	13.75 करोड़ रुपए
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26(1 अप्रैल से अब तक)	457 प्रकरण	22.85 करोड़ रुपए

क्या है योजना

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में कृषक परिवार को आर्थिक सहायता देना है। योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के ऐसे कृषक पात्र हैं, जिनका नाम खतौनी में दर्ज हो अथवा जो खेतिहर मजदूर के रूप में कृषि कार्य से जुड़े हों। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है, जबकि आंशिक दिव्यांगता पर निर्धारित अनुपात में धनराशि प्रदान की जाती है। आवेदन तहसील स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

» तेजस,वंदे भारत समेत 63 ट्रेनें 1 से 10 घंटे लेट, सैकड़ों यात्री फंसे

» 1536 यात्रियों ने निरस्त की यात्रा, इंटरव्यू व जरूरी काम पर भी पड़ा असर

» प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। घने कोहरे ने रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तेजस, वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें तक घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। समय से ट्रेनें न पहुंचने के कारण यात्री आगे की कनेक्टिंग ट्रेनें नहीं पकड़ पा रहे, वहीं नौकरी और इंटरव्यू जैसे जरूरी कार्यों पर भी बड़ा असर पड़ा है। ठिठुरन भरी सर्दी में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर कई-कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को कानपुर सेंट्रल पर 63 ट्रेनें 1 से 10 घंटे तक लेट पहुंचीं। स्थिति इतनी गंभीर रही कि 1536 यात्रियों को अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी। दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत 10 घंटे की देरी से सुबह 5:08 बजे पहुंची, जबकि दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 5 घंटे लेट रात 1:38 बजे स्टेशन पहुंची। सियालदह राजधानी 5:50 घंटे, हावड़ा राजधानी 5 घंटे, नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल 8:35 घंटे और बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 10 घंटे देरी से चली।इसके अलावा काशी महानंदा एक्सप्रेस 9 घंटे, श्रमशक्ति एक्सप्रेस लगभग 6 घंटे, नेताजी एक्सप्रेस 7 घंटे, दूरंतो एक्सप्रेस 7 घंटे और स्वर्ण शताब्दी 1 घंटे से अधिक लेट रही। रेलवे प्रशासन का कहना है कि कोहरे की गंभीर स्थिति के चलते सावधानीवश ट्रेनों की स्पीड सीमित रखी जा रही है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

धर्म विशेष के आराध्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, भीम कथा वाचिका ने पुराना वीडीओ होने की कही बात
आक्रोशित लोगों ने जताई नाराजगी, पुलिस ने दर्ज किया केस, दो लोग हिरासत में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सात दिवसीय बौद्ध कथा में कथावाचक द्वारा धर्म विशेष के आराध्यों के विरुद्ध बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर देकर भीम कथा आयोजक, कथा वाचिका के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने दो लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।

रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलखानपुर गांव में स्थित अंबेडकर पार्क में धम्म देशना संविधान वाचन एवं महापुरुषों की जीवन गाथाओं का सात दिवसीय आयोजन चल रहा था। इसी दौरान कथा वाचिका अर्चना सिंह बौद्ध निवासी हाथरस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालाकि स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो के अनुसार यही कथा वाचिका एक धर्म विशेष के देवी- देवताओं के विरुद्ध बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहीं हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों में जनाक्रोश देखने को मिला। नाराज लोगों ने तरह-तरह की बातें कहीं और मामले में कार्यवाही की मांग करने लगे। तो वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता शिवम सिंह, सुंदरम सिंह, अरविंद सिंह इत्यादि ने नाराजगी प्रकट की। हवासपुर निवासी शिवम बाजपेई ने रसूलाबाद थाने में दी गई तहरीर में बताया कि मंच से कथा वाचिका अर्चना बौद्ध द्वारा आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया। जिसके चलते पुलिस ने कथावाचिका अर्चना बौद्ध, कथा आयोजक गुलाब राम व कमेटी के अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध केस दर्ज किया। वहीं इस संदर्भ में मलखानपुर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जो मंच दिख रहा है वह उनके गांव का नहीं है बल्कि उनका पुराना वीडियो है। उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। इसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

उक्त संदर्भ में पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि रसूलाबाद थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में निष्पक्ष जांच कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आये दिन जाम के झाम से परेशान अकबरपुर के वाशिंदे

» अनंतराज हॉस्पिटल बना मुसीबत, जिम्मेदार विभाग मौन

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र में स्थित अनंतराज हॉस्पिटल इन दिनों इलाज से ज़्यादा जाम और हादसों की वजह बनता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हॉस्पिटल के सामने डबल सर्विस लेन रोड होने के बावजूद अवैध पार्किंग के कारण रोज़ाना जाम लगता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।स्थानीय लोगों के अनुसार, एक सर्विस लेन पर अनंतराज हॉस्पिटल का कथित कब्ज़ा है, जहां हॉस्पिटल से जुड़ी गाड़ियां 365 दिन खड़ी रहती हैं।जब दूसरी सर्विस लेन पर भी हॉस्पिटल की गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, तो पूरी सड़क जाम हो जाती है, जिससे न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी मार्ग से जिले के लगभग सभी आलाधिकारी प्रतिदिन गुजरते हैं, इसके बावजूद अनंतराज हॉस्पिटल के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर, पुल के नीचे आम लोगों के चालान काटने में प्रशासन एक मिनट भी नहीं लगाता, लेकिन हाइवे पर खड़ी हॉस्पिटल की गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह सवाल अब आम जनता पूछ रही है।

बिना पार्किंग कैसे चल रहा हॉस्पिटल

ग्रामीणों का कहना है कि अनंतराज हॉस्पिटल के पास पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है,इसके बावजूद हॉस्पिटल मानकों को ताख पर रखकर संचालित किया जा रहा है। हाइवे पर खड़ी गाड़ियां यातायात नियमों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। लोगों का सवाल है कि बिना पार्किंग सुविधा के हॉस्पिटल को संचालन की अनुमति कैसे मिली? और आखिर किसके संरक्षण में यह सब चल रहा है?

सीएमओ, आरटीओ, एनएचएआई पर उठे सवाल

लोगों ने सीएमओ, आरटीओ, एनएचएआई और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती, तो जाम और हादसों से बचा जा सकता था।अब जनता पूछ रही है सवाल

अनंतराज हॉस्पिटल की गाड़ियां हाइवे पर कैसे खड़ी रहती हैं?

आम जनता का चालान तुरंत, लेकिन हॉस्पिटल पर कार्रवाई क्यों नहीं?

बिना पार्किंग के हॉस्पिटल को मान्यता किस आधार पर मिली? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? जाम से त्रस्त ग्रामीण अब प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

अकबरपुर ईओ आशीष ने बताया है की मुनादी कराई गई थी मै बेड रेस्ट में हूं,जैसे मै आता हूँ टीम गठित हो गई है जिला प्रशासन और नगर पंचायत की टीम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जायेगा। ये आज अंनतराज हॉस्पिटल को नोटिस जारी करने की बात कही है ।

वहीं , इस संबंध में अस्पताल संचालक अमित कटियार से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

माता पिता की सेवा ही जीवन में सर्वोपरि है

» स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के देवीपुर स्थित मां गुमता रज्जन आश्रम में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रामअवतार के माता-पिता की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुजुर्गों, मनीषियों व मेधावियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जालौन गरौठा लोकसभा से सांसद नारायणदास अहिरवार, जिलाध्यक्ष अरुण कुमार, बबलू राजा,सपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र पाल सिंह मनु यादव,हाजी फैजान खान, रुबीना खातून,यादव महासभा के लाल बहादुर आदि रहे। इस दौरान मनीषियों,बुजुर्गों का अंगवस्त्र भेंटकर सम्मान किया गया।वही मेधावियों का भी सम्मान किया गया। यहां सांसद नारायणदास अहिरवार ने कहा कि माता पिता की सेवा जीवन में सर्वोपरि है।इससे बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है इसलिए हम सभी को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा, पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र पाल सिंह मनु, रुबीना खातून ने भी माता पिता के सम्मान में अपने विचार व्यक्त किए। युवा नेता विकास सिंह मलासा, बनारसी बाबू गोपाल, एक उम्मीद के जिलाध्यक्ष चरण सिंह यादव, शिव गोपाल शर्मा,सुंदर सिंह कल्लू भोला गुप्ता समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादकः** अनूप कुमार **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 । **Email:** swarajindia2023@gmail.com । **Mob:** 7800009853, । **Website:** www.swarajindianews.com । (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

बॉलीवॉल प्रतियोगिता का समापन, सैफई बना विजेता

मंत्री ने कहा, खेल में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मीनापुर गांव में सुभाष बॉलीवॉल क्लब द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय बॉलीवॉल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हुआ। इस अवसर पर सेमी फाइनल व फाइनल मैच खेले गए।फाइनल मुकाबला सैफई के पक्ष में रहा। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी,नगद पुरस्कार व उपहार दिए गए।

दो दिवसीय बॉलीवॉल प्रतियोगिता के दूसरे व अंतिम दिन खेल की शुरुआत ग्रामीण आंचल की सेमीफाइनल से हुई।पहला सेमीफाइनल मीनापुर और टाइटन क्लब बरौर के मध्य खेला गया। मुकाबले में मीनापुर ने टाइटन क्लब बरौर को 21–15 तथा 21–18 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच पुखरायां व पटेल क्लब बरौर के मध्य खेला गया।जिसमें पटेल क्लब बरौर ने मीनापुर को 21–15 व 21–14 से परास्त किया।फाइनल मैच पटेल क्लब बरौर व मीनापुर के बीच खेला गया। जिसमें पटेल क्लब बरौर ने मीनापुर को 21–18 तथा 21–17 से परास्त कर मुकाबला जीत लिया।शहरी आंचल में पहला सेमीफाइनल मैच अर्मापुर कानपुर व सैफई के मध्य खेला गया। मुकाबले में सैफई ने अर्मापुर को 20–22, 21–15 तथा 19–17 से पराजित कर फाइनल मैच में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल महदेवा व लखनऊ के मध्य खेला गया। मुकाबले में महदेवा ने लखनऊ को 21–19 तथा 25–23 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया।तत्पश्चात फाइनल मुकाबला सैफई और महदेवा टीमों के मध्य हुआ। रोमांचक मुकाबले में सैफई ने महदेवा को 25–22 से पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम की। बॉलीवॉल प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका अजय चंदेल,रीतेश सचान, अजीत चतुर्वेदी तथा देवेंद्र सचान ने निभाई वहीं कमेंट्रेटर की भूमिका नागेश सचान,जे डी सचान, सूर्यकांत मिश्रा तथा तालिब ने निभाई।प्रतियोगिता के समापन पर विजेता व उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया।मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिलाध्यक्ष रेणुका सचान तथा विशिष्ट अतिथि संजय सचान, सर्वेंद्र सचान, डॉ. सोनेलाल सचान, नीतम सचान ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी,नगद पुरस्कार तथा उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया।मौजूद खिलाड़ियों तथा लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं बल्कि स्थानीय समाज में भाईचारे,एकता और खेल संस्कृति को भी मजबूत करती हैं। खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। वॉलीबॉल क्लब के अध्यक्ष शिवकुमार सचान ने बताया कि बॉलीवॉल इस क्षेत्र का पारंपरिक खेल है और समिति पिछले कई वर्षों से इस प्रतियोगिता का नियमित आयोजन कर रही है ताकि बच्चों से लेकर वरिष्ठ खिलाड़ियों तक को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके ।

लखनऊ का सहभोज और यूपी की राजनीति

क्या लखनऊ में ब्राह्मण संतुलन की नई बिसात बिछ रही है?

सीएम योगी के ब्राह्मण और ठाकुर विधायक अलग-अलग लामबंद होने से राजनीतिक पारा गर्म

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार छोटी दिखने वाली घटनाएं बड़े सियासी संकेत दे जाती हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में हुआ एक सहभोज इन दिनों ऐसे ही संकेतों की वजह से चर्चा में है। कुशीनगर से भाजपा विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर 22 दिसंबर की शाम आयोजित इस कार्यक्रम को भले ही निजी और पारिवारिक बताया गया हो, लेकिन इसमें शामिल चेहरों, समय और माहौल ने इसे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

सूत्रों के अनुसार, इस सहभोज में करीब 35 से 40 विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। इनमें बड़ी संख्या में भाजपा के ब्राह्मण विधायक और एमएलसी मौजूद थे, जबकि कुछ अन्य दलों के ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने भी सबका ध्यान खींचा। मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्र, देवरिया से डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, तरबगंज से प्रेम नारायण पांडेय, बदलापुर से रमेश मिश्र, महनौन से विनय द्विवेदी और एमएलसी साकेत मिश्र जैसे नामों ने इस जुटान को सियासी तौर पर अहम बना दिया। भोजन में लिट्टी-चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया, जिसे आयोजकों ने सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर पेश किया।

यूपी विधानसभा में इस समय ब्राह्मण विधायकों की संख्या 52 बताई जाती है, जिनमें से 46 भाजपा से हैं। यह आंकड़ा सत्ता पक्ष में इस समाज के प्रभाव को रेखांकित करता है। इसके बावजूद, पार्टी और सरकार के भीतर सामाजिक संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुर्मी समाज से आने वाले नेता को मिलने के बाद यह भावना और गहरी हुई कि संगठनात्मक स्तर पर ब्राह्मण नेतृत्व की भूमिका अपेक्षाकृत कम हो रही है।राज्य की राजनीति में ब्राह्मण समाज का इतिहास लंबा और प्रभावशाली रहा है। आजादी के बाद दशकों तक सत्ता की धुरी इसी नेतृत्व के इर्द-गिर्द घूमती रही। 1990 के दशक में मंडल राजनीति के उभार से समीकरण बदले, लेकिन ब्राह्मण समाज पूरी तरह हाशिये पर नहीं गया। समय-समय पर उसने नए राजनीतिक गठबंधनों के साथ अपनी भूमिका बनाए रखी। यही वजह है कि आबादी में 8 से 10 फीसदी माने जाने के बावजूद राजनीतिक प्रभाव कहीं अधिक रहा है।

चुनावी आंकड़े भी इस प्रभाव की पुष्टि करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 83 फीसदी ब्राह्मण मतदाताओं ने भाजपा का समर्थन किया था, जो 2022 में बढ़कर लगभग 89 फीसदी तक पहुंच गया। प्रदेश की 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर और प्रयागराज जैसे जिलों में ब्राह्मण आबादी 15 फीसदी से ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में लखनऊ का यह सहभोज केवल सामाजिक मेल-मिलाप भर मानने को कई राजनीतिक विश्लेषक तैयार नहीं हैं।सूत्रों के मुताबिक, बैठक में खुलकर राजनीति पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दों और हालिया घटनाओं को लेकर चिंता जरूर जताई गई। समाज के साथ कथित उपेक्षा या अन्याय के मामलों में संगठित प्रतिक्रिया देने और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने पर सहमति बनी। कमजोर वर्ग की मदद के लिए वकीलों, डॉक्टरों, रिटायर्ड अधिकारियों और समाज के प्रभावशाली लोगों को जोड़कर एक व्यवस्थित ढांचा बनाने पर भी विचार हुआ।सरकार की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क प्रतिक्रियाएं आईं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का मिलना-जुलना स्वाभाविक है और इसे जातीय चश्मे से देखना गलत है। सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं ने भी इसी तरह की दलील दी।विपक्ष ने इसे भाजपा का आंतरिक मामला बताते हुए तंज कसा। समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसी बैठकों का मतलब है कि पार्टी के भीतर कहीं न कहीं असंतोष मौजूद है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की बेचैनी के तौर पर देखा जा सकता है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सहभोज अपने आप में कोई बड़ा आंदोलन नहीं, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि जातीय संतुलन का सवाल एक बार फिर केंद्र में आ रहा है। हाल के महीनों में ठाकुर और कुर्मी समाज से जुड़े कार्यक्रमों की चर्चाओं के बीच ब्राह्मण विधायकों की यह जुटान सत्ता के भीतर बदलते समीकरणों की ओर इशारा करती है।

2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैयारियां हमेशा पहले शुरू हो जाती हैं। लखनऊ की उस शाम का सहभोज इसी शुरुआती सियासी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। सहभोज खत्म हो चुका है, लेकिन उससे उठी राजनीतिक चर्चा फिलहाल थमती नहीं दिख रहा है।

विवाद के बाद कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज से मांगी माफी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मथुरा।वृंदावन के चर्चित कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय अपने एक पुराने कथन को लेकर उपजे विवाद के बाद सामने आए हैं। 'यादवों का भगवान ने नाश किया' जैसे कथन से आहत यादव समाज की भावनाओं पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद जताते हुए माफी मांगी है। बुधवार को जारी एक वीडियो संदेश में इंद्रेश उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाना कभी नहीं रहा।

इंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि यदि उनकी किसी भी बात से यादव समाज या किसी भी भक्त के हृदय को पीड़ा पहुंची है, तो वह उसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं। उन्होंने कहा कि जिस कथन को लेकर विवाद हुआ, वह चार-पांच साल पुरानी एक कथा के संदर्भ में था, जब किसी राजघराने के व्यक्ति द्वारा व्यक्त किए गए भावों को उन्होंने कथा के दौरान कह दिया था। बाद में जब उन्हें इस पर आपत्ति का अहसास कराया गया, तो उन्होंने आगामी कथाओं में उस बात को स्पष्ट कर दिया।

कथावाचक ने कहा कि विवाद में पड़ना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। 卐सभी हमारे हैं, पूरा भारत हमारा है,卐 कहते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके स्वयं के कई यादव मित्र हैं और वे यादव समाज के प्रति सदैव सम्मान भाव रखते हैं। उन्होंने अपनी कथाओं में यादवों की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी वे कथा में 卐यादव पति यादव राय, यादव पति जगत राय卐 जैसे पदों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण को स्मरण करते हैं।

इंद्रेश उपाध्याय ने अंत में दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल कथा के संदर्भ में भाव प्रकट करना था, न कि किसी समाज की गरिमा को कम करना। उन्होंने यादव समाज से पुनः क्षमा मांगते हुए कहा कि यदि उनकी किसी भी बात से किसी को ठेस पहुंची है, तो वे उसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं और भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने का प्रयास करेंगे।

सीएमओ जांच में 'सिस्टम' कटघरे में

अफसर, लिपिक और दलालों की तिकड़ी पर शिकंजा

70-75 प्राइवेट अस्पतालों की सील खोलने में 'लेन-देन' का आरोप

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर गंभीर आरोपों के भंवर में फंस गई है। सीएमओ अयोध्या डॉ. सुशील कुमार बानियान के खिलाफ शासन स्तर से चल रही जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। जांच टीम ने इस बहुचर्चित प्रकरण में डीपीएम सीएमओ कार्यालय के लिपिक विजय कुमार और योगेन्द्र तिवारी को बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ तलब कर लिया है। जांच टीम की अध्यक्षता कर रहीं निदेशक पैरामेडिकल डॉ. रंजना खरे ने साफ संकेत दे दिए हैं कि यह जांच केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर छिपे खेल को बेनकाब करने की कवायद है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार अयोध्या में 70 से 75 निजी अस्पतालों को पहले नियमों का हवाला देकर सीज किया गया और फिर कथित तौर पर मोटी रकम लेकर उन्हीं अस्पतालों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई। सवाल यह है कि अगर अस्पताल नियम विरुद्ध थे तो उन्हें खोला क्यों गया? और अगर नियम पूरे थे तो सीज क्यों किया गया?

जांच टीम ने सीज किए गए सभी अस्पतालों से जुड़े पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है नोटिस, सीलिंग आदेश, निरीक्षण रिपोर्ट, और पुनः अनुमति से जुड़े कागजात।

सूत्रों के मुताबिक, दस्तावेज़ों की यह पड़ताल कई अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका को उजागर कर सकती है।

जांच की दिशा देखकर यह कयास तेज हो गए हैं कि मातहतों पर गाज गिराने की तैयारी है और ऊपर तक तार जुड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

बड़ा सवाल- मोहरा कौन, मास्टरमाइंड कौन? क्या डीपीएम और लिपिक सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे? या फिर सीलिंग के नाम पर उगाही का पूरा नेटवर्क सक्रिय था? क्या सीएमओ कार्यालय स्वास्थ्य के नाम पर वसूली तंत्र बन चुका था? और अगर आरोप सही हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

जांच की आंच, सिस्टम की परीक्षा

यह मामला केवल व्यक्तियों का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है, जिसमें मरीज, अस्पताल और नियम तीनों सौदेबाज़ी के मोहरे बन जाते हैं। लखनऊ में दर्ज होने वाले बयान इस प्रकरण की दिशा तय करेंगे। एक बात तय है यदि आरोप सिद्ध हुए, तो अयोध्या की स्वास्थ्य व्यवस्था में यह सबसे बड़ा प्रशासनिक झटका होगा।

अब जनता पूछती है-क्या रामनगरी में इलाज अब नियम से नहीं, रकम से तय होता है? और क्या इस बार जांच सच तक पहुंचेगी या फिर फाइलों में ही दम तोड़ देगी ?

अयोध्या में ओज, राष्ट्रबोध और तालियों की गूंज

अटल स्मृति में काव्य का विराट उत्सव

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या ।प्रभु श्रीराम की पावन धरा अयोध्या स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परिसर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित कवि गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन पूरे हर्षोल्लास, जोश और राष्ट्रभाव के साथ संपन्न हुआ।

पूर्व सांसद लल्लू सिंह के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य आयोजन में देशभर से पधारे कवि-कवयित्रियों ने अपनी ओजपूर्ण, राष्ट्रप्रेरक और समसामयिक कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया ।कवियों ने मंच से आज के भारत का सजीव चित्रण करते हुए राष्ट्र, संस्कृति, लोकतंत्र और सामाजिक चेतना को शब्दों में पिरोया। खचाखच भरे पंडाल में हर कविता के साथ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और वातावरण पूरी तरह काव्यमय हो उठा।

घनघोर कोहरे और ठंड के बावजूद अयोध्या की जागरूक जनता ने सम्मेलन के अंत तक अपनी उपस्थिति बनाए रखी, जो साहित्य और राष्ट्रवादी चेतना के प्रति जनआस्था का परिचायक रही। कार्यक्रम के दौरान जिले का पुलिस प्रशासन एवं अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित रहे, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद नजर आई।

सम्मेलन के समापन अवसर पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने सभी कवियों, अतिथियों और श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर वर्तमान सांसद की अनुपस्थिति श्रोताओं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही।

राम मंदिर: संघर्ष, संकल्प और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ऐतिहासिक गाथा

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया

समीर शाही स्वराज इंडिया

अयोध्या। प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक न्याय और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना की कहानी है। इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराने संघर्ष, आस्था की परीक्षा, कानूनी लड़ाई और अंततः विजय के स्वर्णिम क्षणों से होकर गुजरा है। राम जन्मभूमि का विवाद 16वीं सदी में तब शुरू हुआ, जब मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा कथित रूप से प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात सामने आई। इसके बाद यह स्थल आस्था और राजनीति के टकराव का केंद्र बना रहा। पीढ़ियां बदलीं, शासन बदले, लेकिन रामलला की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। यह फैसला केवल कानूनी नहीं, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की सदियों पुरानी आस्था का सम्मान था।

हर ओर 'जय श्रीराम' की गूंज

प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिर मार्गों को आकर्षक लाइटिंग, भगवा बैनरों और धार्मिक प्रतीकों से सज चुकी है। मंदिर परिसर के आसपास आध्यात्मिक उल्लास और सुरक्षा के कड़े इंतजाम साफ नजर आते हैं। हर ओर 'जय श्रीराम' की गूंज है। राम मंदिर निर्माण ने अयोध्या के स्थानीय व्यापारियों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। फूल-माला विक्रेता नरेश कुमार बताते हैं कि मंदिर बनने के बाद उनकी जिंदगी में 99 प्रतिशत बदलाव आया है। पहले संघर्ष था, आज स्थिरता है। रोज 2ङ्क3 क्विंटल फूल-माला बिक जाती है। अब हर महीने 50 से 60 हजार रुपये की कमाई हो जाती है, वे गर्व से कहते हैं। मंदिर निर्माण के बाद उनका परिवार स्थायी रूप से अयोध्या में बस सका। 35 वर्षों से फूल बेच रहे संजय भी अयोध्या के बदलाव के साक्षी हैं। वे कहते हैं, अयोध्या पूरी तरह बदल गई है। यह विकास अभूतपूर्व है। देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्री हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं।

आस्था से अर्थव्यवस्था तक

राम मंदिर आज केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि अयोध्या की सामाजिक और आर्थिक रीढ़ बन चुका है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, फूल, प्रसाद, गाइड–हर क्षेत्र में रोजगार और सम्मान दोनों बढ़े हैं।

राम मंदिर निर्माण: एक नजर में

- 25 मार्च 2020-टेंट से अस्थायी मंदिर में रामलला की विधिवत विराजमान
- 5 अगस्त 2020- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन
- 22 जनवरी 2024- भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा
- 14 अप्रैल 2025- मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना
- 5 जून 2025- प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना
- 25 नवंबर 2025 -मुख्य गुंबद पर भव्य ध्वजारोहण

राष्ट्र की आत्मा का जीवंत प्रतीक

राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में वह अध्याय है, जहां आस्था ने धैर्य रखा, न्याय ने रास्ता दिखाया और संस्कृति ने विजय प्राप्त की। अयोध्या अब केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का जीवंत प्रतीक बन चुकी है।

अयोध्या में सरोज कौशल को श्रद्धांजलि, न्याय की गूंज उठी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या ।शहर के गांधी पार्क, सिविल लाइंस में गुरुवार शाम उस दर्द की आवाज गूंजी, जिसे अब सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि न्याय चाहिए। निर्मला हॉस्पिटल की कथित लापरवाही से मृत श्रीमती सरोज कौशल को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक एकत्र हुए ।सभा में उपस्थित लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूरे वातावरण में शोक, आक्रोश और सवाल एक साथ महसूस किए गए। नागरिकों का कहना था कि यह सिर्फ एक महिला की मौत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता का परिणाम है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोगों ने दो टूक कहा कि जब तक इस मामले में जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक सरोज कौशल को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती ।सभा में न्याय दो, दोषियों पर कार्रवाई हो जैसे स्वर बार–बार गूंजते रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी डॉक्टरों व अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े।

बिना नया अकाउंट बनाए बदल सकेंगे ईमेल पता !

पुरानी और बेढंगी जीमेल आईडी से मिलेगी राहत

» फिलहाल यह फीचर लाइव नहीं हुआ है, लेकिन सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में इसका दिखना इस बात का संकेत है कि कंपनी इस पर गंभीरता से काम कर रही है

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।अगर आप भी स्कूल या कॉलेज के समय बनाई गई अजीब सी जीमेल आईडी से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए सुकून देने वाली है। प्रोफेशनल जीवन में अक्सर ऐसे यूजरनेम शर्मिंदगी का कारण बन जाते हैं, लेकिन अब इस समस्या का समाधान जल्द सामने आ सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2026 में गूगल एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है, जिससे यूजर्स बिना नया अकाउंट बनाए अपना जीमेल एड्रेस बदल सकेंगे।अब तक गूगल अकाउंट सीधे ईमेल एड्रेस से जुड़ा होता था। ऐसे में अगर किसी को अपनी जीमेल आईडी बदलनी होती थी, तो उसे नया अकाउंट बनाना पड़ता था और पुराने ईमेल, फाइलें व डाटा पीछे छूट जाते थे। यही वजह थी कि लाखों यूजर्स सालों तक पुराने और अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करने को मजबूर थे।

क्या है नया अपडेट ?

टेक वेबसाइट नाइन टू फाइव गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल ने अपने हिंदी सपोर्ट पेज में एक नए सिस्टम का जिक्र किया है। इस सिस्टम के जरिए यूजर्स को अपना जीमेल एड्रेस बदलने की अनुमति दी जाएगी।

सबसे अहम बात यह है कि इस प्रक्रिया में पुराना डाटा, ईमेल और फाइलें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।

गूगल के सपोर्ट पेज के अनुसार, यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। यूजर को एक नया जीमेल एड्रेस चुनने का विकल्प मिलेगा। नया एड्रेस बनने के बाद पुराना ईमेल एड्रेस 'उपनाम' की तरह काम करेगा। यानी यूजर नए और पुराने दोनों एड्रेस से लॉग इन कर सकेगा। पुराने एड्रेस पर आए मैसेज और उससे जुड़ा सारा डाटा सुरक्षित रहेगा।

जीमेल बदलने की होगी सीमा

हालांकि यह सुविधा बेहद फायदेमंद है, लेकिन इसके लिए गूगल ने सख्त नियम भी तय किए हैं। यूजर हर 12 महीने में केवल एक बार ही अपना जीमेल एड्रेस बदल सकेगा। इसके अलावा, पूरे जीवनकाल में अधिकतम तीन बार ही एड्रेस बदलने की अनुमति होगी। इसलिए नया यूजरनेम चुनते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी।

फिलहाल यह फीचर लाइव नहीं हुआ है, लेकिन सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में इसका दिखना इस बात का संकेत है कि कंपनी इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2026 तक इसे दुनिया भर में लॉन्च किया जा सकता है।

पुरानी ईमेल आईडी से परेशान लोगों के लिए यह अपडेट किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा। वर्षों से एक गलत फैसले का बोझ ढो रहे यूजर्स को आखिरकार नई और प्रोफेशनल पहचान मिलने की उम्मीद जगी है।

28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले, 14 चौकी इंचार्ज हटे 3 लाइन हाजिर

» अयोध्या एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर का बड़ा एक्शन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या।जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। एसएसपी के आदेश पर 28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, जबकि 14 चौकी इंचार्ज बदले गए हैं। इसके साथ ही 3 चौकी इंचार्जों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस लाइन, कोतवाली अयोध्या, रामजन्मभूमि थाना, कैंट, रुदौली, बीकापुर, कुमारगंज, तारून, गोसाईगंज, हैदरगंज, पटरगा और इनायतनगर समेत कई थानों में तैनात उपनिरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई उपनिरीक्षकों को महत्वपूर्ण चौकियों की कमान दी गई है, जबकि कुछ को थानों से हटाकर पुलिस लाइन या अन्य स्थानों पर तैनात किया गया है।इस फेरबदल में नयाघाट, रानोपाली, दर्शननगर, हनुमानगढ़ी, कटरा, मोतीगंज, साहबगंज, हाईवे, चिलबिली, बारून, नयागंज, शुजागंज, सदर बाजार, महबूबगंज, रामपुरभगन, हवाई पट्टी, सती चौरा, जिला कारागार और महिला रिपोर्टिंग चौकी समेत कई अहम चौकियां शामिल हैं। महिला उपनिरीक्षकों को भी नई तैनाती दी गई है।पुलिस प्रशासन के अनुसार यह बदलाव कार्यकुशलता बढ़ाने, निष्पक्ष पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। जिन चौकी इंचार्जों को लाइन हाजिर किया गया है, उनके कार्यों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।इस व्यापक फेरबदल के बाद जिले में पुलिसिंग को लेकर अधिक सक्रियता, जवाबदेही और सख्ती देखने को मिल सकती है। पुलिस महकमे में एसएसपी के इस कदम को साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि लापरवाही पर कार्रवाई तय है।